International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2025; 8(1): 533-538
www.theeconomicsjournal.com
Received: 06-06-2025
Accepted: 24-06-2025

विष्णु दत्त
शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ० आलोक सिंह
सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
विष्णु दत्त
शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

वित्तीय समावेशन में लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका: माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का अध्ययन

विष्णु दत्त, डॉ० आलोक सिंह

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26179210.2025.v8.i1.565

सारांश
वित्तीय समावेशन आज भारत के समग्र विकास की एक प्राथमिक शर्त बन चुका है, और इसमें लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका अत्यंत केंद्रीय हो गयी है। ये उद्योग न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। हालांकि, पूंजी की सीमित पहुँच, औपचारिक बैंकिंग से दूरी, और तकनीकी जानकारी की कमी लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास को बाधित करती है। ऐसे परिदृश्य में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ (MFIs) एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी हैं, जो वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का कार्य करती हैं। यह शोधपत्र भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) की भूमिका और माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण करता है। भारत की विशाल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब भी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। ऐसे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एक सेतु का कार्य करती हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में सहायक हैं। इस शोध-प्रपत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस शोध के माध्यम से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, और वित्तीय संस्थाओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और माइक्रो फाइनेंस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर, नीतिगत सहयोग से समावेशी आर्थिक विकास को सशक्त किया जा सकता है। यह शोध वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सार्थक योगदान प्रस्तुत करता है।

कूटशब्द : माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस संस्था, लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग।

1. प्रस्तावना
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उस देश में स्थापित बड़े-बड़े उद्योगों से नहीं होता है, अपितु लघु एवं मध्यम उद्योगों से होता है। लघु एवं मध्यम उद्योग किसी भी स्वरुप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होतीं हैं जब राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट व्याप्त होता है तब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सकरात्मक रूप से वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत बीते कुछ गत वर्षों के कोरोना काल के दौरान देखने को मिला है। भारत भी उन अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है जिसने कोरोना काल के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों के द्वारा पटरी पर लाने का प्रयास किया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों की परिभाषा देशानुसार परिवर्तित होती रहती है। भारत में जब पहली बार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 आया तो उसने विनियोग एवं आवर्त के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों की परिभाषा व्याख्यित की, जो समयानुसार संशोधित भी होती रही।

संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण - संघ बजट 2025 के अनुसार

उद्यम श्रेणी	वर्तमान निवेश सीमा	संशोधित निवेश सीमा	वर्तमान टर्नओवर सीमा	संशोधित टर्नओवर सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro)	₹1 करोड़ तक	₹2.5 करोड़ तक	₹5 करोड़ तक	₹10 करोड़ तक
लघु उद्यम (Small)	₹10 करोड़ तक	₹25 करोड़ तक	₹50 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium)	₹50 करोड़ तक	₹125 करोड़ तक	₹250 करोड़ तक	₹500 करोड़ तक

Source: https://www.smechamberofindia.com/about-msme-in-india.php

माइक्रो फाइनेंस का अर्थ है—ऐसी वित्तीय सेवाओं का वह समूह जो विशेष रूप से उन गरीब और वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुँच पाते। इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, बचत खाता, बीमा, धन प्रेषण, और वित्तीय परामर्श शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों, विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण गरीबों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों का अंशदान सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात एवं रोजगार सृजन में क्रमशः 30%, 45% एवं 66% के लगभग है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अंशदान में विकसित देशों की तुलना में लगभग 15-20 प्रतिशत की कमी है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों के वृहत रूप से विस्तार की संभावना का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

किन्तु, इन उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या है - वित्त की कमी। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली इन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाती है। उच्च ब्याज दरें, जमानत की मांग, जटिल प्रक्रियाएँ और वित्तीय साक्षरता की कमी जैसी बाधाएँ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों को औपचारिक वित्तीय ढाँचे से दूर कर देती हैं। यहीं पर माइक्रो फाइनेंस की भूमिका उभर कर सामने आती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों के लिए माइक्रो फाइनेंस एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह उन्हें प्रारंभिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, नवाचारों के लिए निवेश तथा विस्तार के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराता है। विशेषकर महिलाओं के स्वावलंबन, ग्रामीण उद्यमिता और कुटीर उद्योगों के लिए माइक्रो फाइनेंस का प्रभाव व्यापक रूप से देखा गया है।

विभिन्न शोध अध्ययनों के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योंगों के क्षेत्र के विकास में अत्यल्प शोध ही हुए है अतः यह शोध अध्ययन यह जानने में सहायक होगा कि कैसे माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन में बढ़ावा देने के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योंगों के विकास में सहायक होगा तथा यह अध्ययन लघु एवं मध्यम उद्योंगों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की चुनौतियों एवं सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करता है।

2. साहित्य पुनरावलोकन

मल्होत्रा, एम. (2018) ने अपने इस अध्ययन में माइक्रो फाइनेंस को भारत में वित्तीय समावेशन का एक प्रभावी माध्यम बताया है। लेखक के अनुसार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ उन वर्गों तक पहुँच रही हैं जो परंपरागत बैंकिंग प्रणाली से वंचित हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ ऋण नहीं, बल्कि उद्यमिता विकास और सामाजिक समावेशन का साधन है।

राजत देब और देवी बरूआ (2022) द्वारा किए गए इस अध्ययन में कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के सामने आए कार्यशील पूंजी वित्त (WCF) प्रबंधन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। महामारी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अस्तित्व संकट में डाल दिया, परंतु इस अध्ययन में यह बताया गया कि वास्तविक समस्या कार्यशील पूंजी वित्त की उपलब्धता और प्रबंधन में है। इस अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया कि नवाचार और तकनीकी प्रगति के माध्यम से नई रणनीतियाँ अपनाकर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

कुमार एवं बहल (2023) के अनुसार, इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विकास को कैसे प्रभावित करती है। इसमें लगभग 400 प्रतिभागियों में से 221 का डाटा एकत्र किया गया और SPSS सॉफ़्टवेयर द्वारा विश्लेषण किया गया। परिणामतः यह पाया गया कि माइक्रोक्रेडिट, वित्तीय सहायता, और वित्तीय सेवाएँ का लघु एवं मध्यम उपक्रमों की वृद्धि पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि माइक्रोफाइनेंस, उद्यमों को सशक्त बनाकर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायक है।

कपिल गोरा, बरखा ढींगरा एवं महेंद्र यादव (2023) के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्ययन में स्कोपस (Scopus) डेटाबेस से 631 लेखों का चयन कर बिब्लिओमेट्रिक्स (Bibliometrix) और वॉसव्यूअर (VOSviewer) सॉफ्टवेयर की मदद से बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण किया गया। इस शोध में मुख्य रूप से चार विषय सामने आए हैं: वित्तीय पहुँच और योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का प्रदर्शन, एवं माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में नवीनताएँ। बिब्लिओमेट्रिक्स और वॉसव्यूअर जैसे टूल्स से किए गए बिब्लिओमेट्रिक्स विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान निरंतर बढ़ रहा है। अतः भविष्य में वित्तीय समावेशन और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की स्थिरता पर और अधिक शोध की आवश्यकता है।

अश्विनी पांढरे, प्रवीण नायक बेल्लमपल्ली और नीलम यादव (2023) के इस अध्ययन का उद्देश्य था कि माइक्रोफाइनेंस हस्तक्षेप और स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाओं की उद्यमशील भागीदारी किस प्रकार उनके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को प्रभावित करती है। इस अध्ययन में मिश्रित विधियों का उपयोग किया गया, जिसमें

सर्वेक्षण, साक्षात्कार और केस स्टडी के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया, ताकि महिलाओं के अनुभवों और प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि माइक्रोफाइनेंस और उद्यमिता से महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता, सामाजिक सहयोग और आत्मविश्वास में सकारात्मक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

वर्मा, दास और मिश्रा (2024) ने भारत के 9,024 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों पर आधारित WBES 2022 डेटा का उपयोग कर डिजिटल अभिग्रहण के प्रभाव का अध्ययन किया। हेकमैन के दो-चरणीय प्रतिगमन विधि से यह पाया गया कि डिजिटल अभिग्रहण बिक्री और उत्पादकता में विशेषकर बड़े और पुराने उद्यमों में वृद्धि करता है। हालांकि, इससे रोज़गार वृद्धि पर प्रभाव सीमित रहा। इस अध्ययन ने छोटे, युवा और अनौपचारिक उद्यमों में डिजिटल अंतर को उजागर किया।

3. उद्देश्य

- माइक्रो फाइनेंस के सन्दर्भ में लघु एवं मध्यम उद्योगों की अवधारणा को जानना।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा माइक्रो फाइनेंस तक पहुँच बनाने में उत्पन्न समस्याओं की पहचान करना।
- माइक्रो फाइनेंस द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योंगों के विकास में वित्तीय सेवाओं के सुगम संचालन के लिए दृष्टिगत समस्याओं के समाधान के उचित उपायों को जानना।

4. शोध प्रविधि

यह शोध-अध्ययन व्याख्यात्मक प्रकृति का है जिसमें द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। उन समंको का एकत्रीकरण उच्च कोटि के शोध जर्नल्स, सिडबी, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की रिपोर्ट, विभिन्न उच्च मानक सरकारी एवं गैर-सरकारी वेबसाइट्स, समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य द्वितीयक स्रोतों से किया गया है।

5. विश्लेषण एवं निर्वचन

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक उनकी पहुँच सीमित है, वहाँ वित्तीय समावेशन एक आवश्यक रणनीति बन जाती है। इसका मूल उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विशेषकर वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और स्वरोज़गार करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें परंपरागत बैंकिंग प्रणाली द्वारा अक्सर उपेक्षित किया जाता रहा है। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश की GDP का लगभग 30% योगदान देते हैं, और लगभग 45% निर्यात इन्हीं उद्योगों से होते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उद्योग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम वार्षिक रिपोर्ट, 2024)। लेकिन इसके बावजूद, इनकी ऋण तक पहुँच सीमित है, जिससे इनकी वृद्धि बाधित होती है।

वित्तीय समावेशन में लघु एवं मध्यम उद्योगों और माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख चुनौतियाँ

- **संस्थागत संरचना और वित्तीय पहुँच की समस्याएँ**
  लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के सामने सबसे बड़ी चुनौती औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था की जटिलता है। पारंपरिक बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल, क्रेडिट स्कोर, बैलेंस शीट जैसे दस्तावेज़ों की माँग करते हैं, जो असंगठित या नवप्रवेशी उद्यमों के लिए उपलब्ध नहीं होतें है। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ (MFIs) एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभरती हैं, जो बिना कोलेटरल ऋण देती हैं। परंतु, उनकी भी अपनी सीमाएँ होती हैं—जैसे ऋण की न्यूनतम सीमा, सीमित परिचालन क्षेत्र, और पूंजी की कमी।
- **उच्च ऋण लागत और कार्यशील पूंजी का अभाव**
  माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें परंपरागत बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं, जिससे ऋण की लागत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए बढ़ जाती है। प्रायः ये दरें 20 से 26 प्रतिशत तक पहुँच जाती हैं। चूँकि लघु उद्योगों को संचालन के लिए निरंतर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा दी गई ऋण राशि सीमित होती है, इसलिए उनकी उत्पादन, वितरण और वेतन प्रणाली प्रभावित होती है।
- **नियामकीय और पुनर्भुगतान संबंधी बाधाएँ**
  हालांकि रिज़र्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए कुछ नियामकीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, फिर भी ऋण वितरण और वसूली में पारदर्शिता की कमी अब भी बनी हुई है। एकाधिक ऋण प्रदान करने की प्रवृत्ति, ऋण जाल में फँसने की संभावना और पुनर्भुगतान के समय ग्राहकों पर दबाव जैसी स्थितियाँ सामने आती रही हैं। यह न केवल ग्राहकों की स्थिति को अस्थिर बनाती है, बल्कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है।
- **वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता जागरूकता का अभाव**
  ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लघु उद्यमियों में वित्तीय जागरूकता का अभाव है। ऋण की शर्तें, उपयोग की रणनीतियाँ और पुनर्भुगतान की समय-सारणी को समझने में कठिनाई होती है। इसके कारण ऋण का दुरुपयोग, चूक और डिफॉल्ट की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल उनके व्यवसाय को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि माइक्रो फाइनेंस प्रणाली की स्थिरता को भी प्रभावित करता है।
- **डिजिटलीकरण और तकनीकी बाधाएँ**
  डिजिटल फाइनेंस सेवाएँ आज वित्तीय समावेशन का प्रमुख आधार बन चुकी हैं, किंतु ग्रामीण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की डिजिटल पहुँच सीमित है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की उपलब्धता, और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने

में पिछड़ जाते हैं। इससे उन्हें समय पर ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

- **कोविड-19 के प्रभाव और नकदी संकट**
  कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए। उत्पादन लगभग बंद-सा हो गया, बिक्री में काफी गिरावट आ गई और नकदी प्रवाह बंद हो गया। माइक्रो फाइनेंस संस्थान स्वयं भी संकट से जूझ रही थीं, जिससे ऋण वितरण बंद सा हो गया। सरकार द्वारा घोषित सहायता योजनाएँ कई क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सकीं या जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकीं। इससे कई लघु उद्योग स्थायी रूप से बंद हो गए।
- **असंगठित क्षेत्र में डेटा की अनुपलब्धता**
  भारत में अधिकांश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग असंगठित क्षेत्र में हैं, जहाँ उनके वित्तीय प्रदर्शन, श्रमिक संरचना और उत्पादन की जानकारी का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं होता। इससे उन्हें ऋण के लिए उपयुक्त ग्राहक मानना कठिन हो जाता है और माइक्रो फाइनेंस संस्थान या बैंक दोनों उनके साथ जोखिम लेने से कतराते हैं।

वित्तीय समावेशन में लघु एवं मध्यम उद्योगों और माइक्रो फाइनेंस की राह में आने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान

- **वित्तीय उत्पादों का सरलीकरण और अनुकूलन**
  लघु एवं मध्यम उद्योगों की विविध आवश्यकताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाएँ विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ऋण, बीमा और बचत उत्पाद विकसित करें। कार्यशील पूंजी के लिए आसान पुनर्भुगतान विकल्प, ऋण पर लचीली ब्याज दरें, और व्यवसाय-विशिष्ट स्कीमें शुरू की जा सकती हैं। इससे ऋण का उपयोग प्रभावी होगा और पुनर्भुगतान दरों में सुधार आएगा।
- **वित्तीय साक्षरता एवं उद्यमिता शिक्षा का विस्तार**
  सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के संचालकों के लिए वित्तीय शिक्षा आवश्यक है, ताकि वे ऋण प्रबंधन, पुनर्भुगतान योजना, बजट निर्माण, और डिजिटल भुगतान के विषय में जागरूक हो सकें। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर पंचायत स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और व्यवसाय सलाह केंद्र स्थापित करने चाहिए।
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पहुँच और प्रशिक्षण**
  वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटलीकरण अनिवार्य है, परंतु ग्रामीण और लघु उद्योगों तक इसकी पहुँच अभी भी सीमित है। इसके समाधान हेतु मोबाइल ऐप्स को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाना चाहिए और इनका इंटरफ़ेस सरल एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
- **ऋण वितरण तंत्र में पारदर्शिता और निगरानी:**
  माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु नियामकीय तंत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए। ऋण देने की प्रक्रिया, ब्याज दरों की घोषणा, तथा पुनर्भुगतान नीति को स्पष्ट और उपभोक्ता अनुकूल बनाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया तथा नाबार्ड जैसी संस्थाएँ स्थानीय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर नियमित निगरानी रखें और एक केंद्रीकृत डेटा पोर्टल विकसित करें जिसमें सभी ऋण, ग्राहक प्रोफाइल और पुनर्भुगतान विवरण दर्ज हों।
- **सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुँच**
  सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE), स्टैंडअप इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) आदि का लाभ अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जानकारी, प्रक्रिया और सहायता एक ही पोर्टल पर सरल भाषा में उपलब्ध हो। साथ ही, बैंक कर्मियों को भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों के ऋण मामलों में संवेदनशील और प्रशिक्षित बनाया जाए ताकि वे सहायक भूमिका निभा सकें।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों का औपचारीकरण और डेटा एकत्रण**
  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और नि:शुल्क बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्यम औपचारिक क्षेत्र में आ सकें। इसके लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल (जैसे UDYAM पोर्टल) का अधिकतम प्रचार किया जाना चाहिए। औपचारिक पंजीकरण से न केवल डेटा पारदर्शी होगा, बल्कि नीति निर्माताओं को योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में सहायता मिलेगी।
- **आपदा प्रबंधन एवं पुनःस्थापन तंत्र का निर्माण**
  कोविड-19 जैसे संकटों से लघु एवं मध्यम उद्योगों की रक्षा हेतु आपातकालीन सहायता कोष, बीमा योजनाएँ और ऋण स्थगन की स्पष्ट नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। सरकार और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को मिलकर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए संकटकालीन पुनर्पूंजीकरण योजनाएँ लागू करनी चाहिए जिससे संकट के समय व्यवसाय स्थायी रूप से बंद न हों।

6. निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील देश में वित्तीय समावेशन को सशक्त एवं समावेशी आर्थिक विकास का आधार माना जाता है, और इसमें लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) की भूमिका अत्यंत केंद्रीय है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, नवाचार और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, किंतु आज भी ये उद्योग वित्तीय प्रणाली के मुख्यधारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ (MFIs), विशेष रूप से ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, इन उद्योगों के लिए ऋण, बीमा और वित्तीय सेवाओं का वैकल्पिक स्रोत बनकर उभरी हैं।

हालाँकि, उपर्युक्त वर्णित अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केवल माइक्रो फाइनेंस की उपलब्धता भर से लघु एवं मध्यम

उद्योगों के सामने आने वाली समस्याएँ समाप्त नहीं होतीं, बल्कि उच्च ब्याज दरें, सीमित ऋण राशि, कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की भौगोलिक पहुंच की सीमाएँ एक बड़ी चुनौती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, और असंगठित लघु एवं मध्यम उद्योगों का औपचारिक पंजीकरण न होना भी समावेशन के प्रयासों को बाधित करता है।

कोविड-19 ने दिखाया कि केवल ऋण से लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायित्व नहीं मिलता। इसके लिए वित्तीय शिक्षा, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और नीतिगत समर्थन आवश्यक हैं। माइक्रो फाइनेंस को सशक्तिकरण के उपकरण की तरह अपनाकर लघु एवं मध्यम उद्योंगों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सार्थक प्रगति की जा सकती है।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जब तक लघु एवं मध्यम उद्योंगों को समुचित वित्तीय सुविधा, जानकारी और संरचनात्मक समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। लेकिन यदि इन कमियों को दूर कर रणनीतिक दृष्टिकोण से कार्य किया जाए, तो भारत में समावेशी, सतत और लचीला आर्थिक विकास संभव है — जहाँ लघु एवं मध्यम उद्योग सामाजिक-आर्थिक बदलाव के प्रभावी वाहक बन सकें।

7. सीमाएं

- यह अध्ययन केवल द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योंगों और माइक्रो फाइनेंस के संबंध पर उपलब्ध साहित्य सीमितिता।
- समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण अध्ययन कुछ चुनी हुई रिपोर्ट्स और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है।

8. References

1. Ahmed H. Crowdfunding and entrepreneurial/SME finance: Regulatory framework for financial inclusion. J Bank Regul. 2025. https://doi.org/10.1057/s41261-025-00273-2
2. Alom K, Rahman MZ, Khan AI, et al. Digital finance leads women entrepreneurship and poverty mitigation for sustainable development in Bangladesh. J Innov Entrep. 2025;14:34. https://doi.org/10.1186/s13731-025-00471-2
3. Awe T, Omoniyi O. Impact of microfinance on micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Southwest Nigeria. Int J Res Sci Innov. 2023;10:613-619. https://doi.org/10.51244/IJRSI.2023.1011052
4. Deb R, Baruah D. Working capital financing for MSMEs in the pandemic era: Challenges and opportunities. SEDME. 2022;49(2):131-40. https://doi.org/10.1177/09708464221097224
5. Devender K, Kafila G, Goli G, et al. Bibliometric trends in SMEs financial literacy research from 2021 to 2024. Future Bus J. 2025;11:69. https://doi.org/10.1186/s43093-025-00495-w
6. Jalil MF. Microfinance towards micro-enterprises development in rural Malaysia through digital finance. Discov Sustain. 2021;2:55. https://doi.org/10.1007/s43621-021-00066-3
7. Gora K, Dhingra B, Yadav M. A bibliometric analysis of microfinance research using Scopus database. Int J Prof Bus Rev. 2023;8(5):e03592. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.3592
8. Kumar M, Bahl S. Role of microfinance in developing small-medium enterprise (SME) businesses. Int J Res Finance Manag. 2023;6(1):403-407. https://doi.org/10.33545/26175754.2023.v6.i1d.242
9. Lwesya F, Mwakalobo ABS. Frontiers in microfinance research for small and medium enterprises (SMEs) and microfinance institutions (MFIs): A bibliometric analysis. Future Bus J. 2023;9:17. https://doi.org/10.1186/s43093-023-00195-3
10. Lwesya F, Mwakalobo ABS. Frontiers in microfinance research for small and medium enterprises (SMEs) and microfinance institutions (MFIs): A bibliometric analysis. Future Bus J. 2023;9:17. https://doi.org/10.1186/s43093-023-00195-3
11. Malhotra M. Role of microfinance in financial inclusion in India. In: Microfinance and Its Impact on Entrepreneurial Development, Sustainability, and Inclusive Growth. IGI Global; 2018. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5213-0.ch018
12. Pandhare A, Bellampalli PN, Yadava N. Transforming rural women's lives in India: The impact of microfinance and entrepreneurship on empowerment in self-help groups. J Innov Entrep. 2024;13:62. https://doi.org/10.1186/s13731-024-00419-y
13. Sekyen B, Zaphaniah M. Micro-finance and performance of micro, small and medium enterprises in Jos Metropolis. Br J Manag Mark Stud. 2024;7:15-30. https://doi.org/10.52589/BJMMS-KVSZR7UI
14. Singla A, Mahajan P. Growth and financing of MSMEs: A case study of Punjab and Haryana. Asia Pac J Manag Res Innov. 2012;8(3):315-21. https://doi.org/10.1177/2319510X1200800311
15. Verma A, Das KC, Misra P. Digital finance and MSME performance in India: evidence from World Bank Enterprise Survey data. J Econ Stud. 2024. https://doi.org/10.1108/JES-12-2023-0744
16. https://msme.gov.in/documents/reports-and-publications
17. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/careernotices/2310193740Credit%20Potential%20For%20MSME.pdf
18. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035073

19. https://www.sidbi.in/head/uploads/microfinancepulse_documents/MFI-Pulse-Report%20-20th-Edition_compressed.pdf
20. https://www.smechamberofindia.com/about-msme-in-india.php